प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

29.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

मौसम

प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। मंडी जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त–व्यस्त कर दिया है। पिछले आठ घंटों में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि एक अन्य अब तक लापता है। इधर चंडीगढ़–मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और मंडी–पठानकोट राजमार्ग भी कई स्थानों पर भूस्खलन से यातायात के लिए बाधित है।

–विस्तृत ब्यौरे के हमारे मंडी जिला संवाददाता....

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बीती रात से जारी मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन कोबुरी तरह प्रभावित किया है। भारी वर्षा से हुई तबाही में अब तक तीन लोगोंकी मौत हो चुकी है जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। मृतकों में मंडी शहर के जेलरोड निवासी बताए गए हैं। एक का शव मलबे में दबा मिला है जबकि अन्य दो की तलाशजारी है। वर्षा इतनी भीषण रही कि मंडी जिला की प्रमुख सड़कें जेलरोड और हॉस्पिटल रोड उफनते नालों के कारण नदी जैसी बन गई। मलबा बहकर सड़कोंपर आ गया जिससे यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया। कई घरों की निचली मंजिलों में कीचड़ और पानी भर गया दो पहिया और चार पहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुएहैं। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया हैलेकिन लगातार हो रही वर्षा राहत कार्यों में बड़ी बाधा बनी है। उधर चंडीगढ–मनाली उच्च राष्ट्रीय मार्ग और मंडी–पठानकोट उच्च राष्ट्रीय मार्ग पर कई स्थानों पर भू स्खलन हुआ है जिस कारण दोनों पर यातायात पूरी तरह से बंद है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और पुलिस राहत कार्यों में जुडी है जबकि एन डी आर एफ को भी सतर्क रहने को कहा गया है।

भारी बारिश के चलते मंडी सब डिवीजन के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रखे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात से प्रदेश में हो रहा नुक्सान चिंताजनक है और इस मुश्किल घड़ी में सावधान रहने की आवश्यकता है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

मंत्रिमण्डल

प्रदेश सरकार मानसून में हुए नुक्सान से प्रभावित परिवारों को वर्ष 2023 की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की चार दिवसीय बैठक के पहले दिन कल ये निर्णय लिया गया। आपदा राहत के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए एक लाख रूपए दिए जाएंगे।

इसी प्रकार घरों का सामान बहने, खेती योग्य भूमि के क्षतिग्रस्त होने, फसल व पशुधन क्षति, और मकानों में सिल्ट आने पर भी राहत राशि घोषित की गई है। मंत्रिमंडल ने भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे घोटाले पर रोक लगाने के लिए एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज भी राज्य सचिवालय में केबिनेट बैठक जारी रहेगी।

किसान प्रदर्शन

वन भूमि में अतिक्रमण मामलों में सेब के पेड़ों के कटान के प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिमला के पूर्व उपमहापौर टिकेन्द्र सिंह पंवर की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं। हाल ही में शिमला जिला के कई क्षेत्रों में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार हजारों सेब के पेड़ काटने की प्रक्रिया जारी थी जिसे टिकेंद्र पंवर ने अपनी याचिका में पर्यावरण सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।

ये हमारे पहाड़ियों के लिए जो हम हिमाचल में हैं एक इमोशनल सवाल भी था। बहुत सारे तोये जंगल तो सरकार के पास ही थे तो इनका काटना बिल्कुल वाजिब नहीं था। उसमें हमने कहा कहा था तो हार्वेस्ट सीजन है तो आप उसके प्रोडयूस का इस्तेमाल कीजिए लारजल इंटरेस्ट क्या है इसमें इनवायरमेंट इम्पेस्ट असेसमेंट होती है। उस इनवायरमेंट इम्पेस्ट असेसमेंट का कोई जिक नहीं है कि इस इम्पेक्ट क्या पड़ेगा हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं पिछले 4–5 सालों से जो हमारे यहां लैंड स्लाइड हैं बाढ़ आ रही है।

इधर वन भूमि से बेदखली, फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने और किसानों–बागवानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ द्वारा शिमला में प्रदेश सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन का आहवान किया गया है।

एचआरटीसी बैठक

हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस अडडा प्राधिकरण की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में जारी है। बैठक में एच आर टी सी को सशक्त बनाने और बसों के बेड़े को बढ़ाने के अलावा कर्मचारियों के वित्तीय लाभों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन इन दिनों लंबित ओवर टाइम, रात्रि भत्ते और चिकित्सा भत्तों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन ने वित्तीय देनदारियां न मिलने पर पहली अगस्त से ओवर टाइम और रात्रि डयूटी न करने का भी फैसला लिया है।

पहाड़ी बोली

न्यू ऐजुकेशन पालिसी 2020 के तहत अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को महीने में एक दिन स्थानीय पहाड़ी बोली सिखाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार महीने के आखिरी शनिवार यानी बैग फ्री डे पर बच्चों में स्थानीय भाषा, संस्कृति और वार्तालाप कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे स्थानों में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है जहां शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों, अंकों या रटने तक सीमित न रहे। पिछले पांच वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, शिक्षार्थी–केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है।